



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032025-261687
CG-DL-E-18032025-261687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]
No. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

सं. 50 / 2024—25

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैराग्राफ 10.12 (घ) में संशोधन—मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार—पत्र (जीईआर) में संशोधित प्रक्रिया।

फा. सं. 01/91/180/18/एएम—17/ईसी(एस).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 10.12(घ) पर नई प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से शामिल करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 10.12(घ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

“घ. मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईआर) के तहत विदेशों में उसी आयातित स्कोमेट वस्तुओं को संबंधित इकाइयों और मरम्मत आपूर्ति शृंखला¹ को निर्यात किए जाने के लिए प्राधिकार—पत्र”

^०संबंधित इकाई का अर्थ भारतीय कम्पनी की प्रत्यक्ष सहायक/विदेशी मूल या भारतीय कम्पनी की विदेशी मूल की अन्य सहायक कम्पनी है।

^१मरम्मत आपूर्ति श्रृंखला का अर्थ (i) प्राधिकृत विक्रेता (ii) मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) जिसके साथ भारतीय कम्पनी ने भारत में मरम्मत हेतु वचनपत्र की शर्तों की परिभाषा देते हुए मास्टर सेवा समझौता/इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता सेवा समझौता/अनुबंध समझौता किया है।

क. भारत में मरम्मत के बाद विदेश में संबंधित इकाइयों^० और मरम्मत आपूर्ति श्रृंखला^१ को आयातित स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात की अनुमति डीजीएफटी द्वारा जारी तिमाही आधार पर पश्च रिपोर्टिंग के अधीन भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए एकमुश्त सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईआर) के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:

- क. अनुबंध समझौता/मास्टर सेवा समझौते (एमएसए) के तहत मरम्मत के उद्देश्य से भारत में नामित/प्राधिकृत मरम्मत सुविधा के लिए स्कोमेट मदों का आयात किया गया था या भारतीय निर्यातक, मरम्मत सुविधा की इकाइयों (यदि निर्यातक से भिन्न हो) और विदेश में 'कार्य विवरण (एसओडब्ल्यू)' / 'कार्य का दायरा' को परिभाषित करने वाली इकाइयों के बीच एक अनुबंध समझौते के तहत आयातित, जिसमें भारत में मरम्मत करने की शर्तें शामिल हैं;
- ख. मदों को विदेशों में केवल संबंधित इकाइयों^० और मरम्मत आपूर्ति श्रृंखला^१ को पुनः निर्यात किया जाना है;
- ग. निर्यातक को वैधता अवधि के दौरान केवल एक बार मरम्मत के बाद निर्यात के लिए पंजीकरण और सामान्य प्राधिकार-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। आगामी निर्यात/पुनः निर्यात पश्च रिपोर्टिंग के अधीन है;
- घ. पहली शिपमेंट के लिए जीईआर के लिए आवेदन करते समय निर्यातक को आयातित वस्तु के लिए प्रविष्टि बिल प्रदान करना अपेक्षित है;
- ड. मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्र, सामान्य प्राधिकार-पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जो इस तरह के निर्यात की तारीख से 30 दिनों के भीतर आगामी पश्च रिपोर्टिंग (रिपोर्टिंग्स) के अधीन होगा;
- च. आगामी निर्यात की अनुमति उसी इकाई और स्थान को दी जाएगी, जिसे मूल रूप से लाइसेंस जारी किया गया है। टिप्पणी: उसी इकाई का अर्थ होगा कि (क) विदेशी खरीदार (ख) परेषिती या मध्यस्थ, यदि कोई हो (ग) अंतिम उपयोगकर्ता बिल्कुल वही है जिसके लिए आवेदक निर्यातक को प्राधिकार-पत्र जारी किया गया है;
- छ. मरम्मत के बाद स्कोमेट मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और मरम्मत कार्य के दौरान कोई मूल्यवर्धन नहीं किया गया है।
- ज. कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र तब नहीं दिया जाएगा जब तक प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार-पत्र को आयातक देश द्वारा निलंबित, संशोधित या निरस्त कर दिया गया हो;
- झ. यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों या उच्च जोखिम वाले देशों/संस्थाओं के लिए कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जैसा कि आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है;
- ज. 'अंतिम उपयोग' और 'अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र' के किसी विवरण की आवश्यकता नहीं होगी;
- ट. विशिष्ट मद और विशिष्ट इकाई (खरीदार/अंतिम उपयोगकर्ता) के लिए जारी किया गया जीईआर लागू नहीं होगा यदि पुनः निर्यात एक अलग आयातित वस्तु या एक अलग इकाई या अधिकृत ओईएम के लिए है। ऐसे मामलों में, या तो एक नया जीईआर प्राधिकार-पत्र लागू किया जा सकता है या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.12(घ) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

ठ. प्रमाणित/अनुमोदित आंतरिक अनुपालन कार्यक्रम या विदेशी कंपनी के आइसीपी के अनुपालन का प्रदर्शन या उस कंपनी के अनुपालन प्रबंधक द्वारा प्रमाणित आइपीसी अनिवार्य होगा [केवल अंतरा—कंपनी स्थानांतरण के लिए]।

ड. आइसीपी अनुपालन के साथ प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईआरो) प्रमाणन अनिवार्य होगा [विक्रेताओं/आइएम को पुनः निर्यात के लिए]।

ख. जीएईआर के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. मद (मदों) के आयात का प्रमाण:

- क. भारत में मदों के मूल आयात के लिए विदेश द्वारा जारी निर्यात प्राधिकार—पत्र (यदि लागू हो);
- ख. दस्तावेजी प्रमाण और/या स्व—घोषणा जिसे मद को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है या भारत के लिए लाइसेंस की आवश्यकता के तहत नहीं रखा गया है;
- ग. प्रविष्टि बिल (पहली बार)

2. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत के लिए दायित्व का प्रमाण

भारतीय निर्यातक और विदेश में इकाई/प्रत्यक्ष सहायक/भारतीय कंपनी की मूल कंपनी या भारतीय कंपनी की विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी/अधिकृत विक्रेता/मूल उपकरण विनिर्माता के बीच अनुबंध समझौता और/या 'कार्य का विवरण (एसओडब्ल्यू)'/मास्टर सेवा समझौता (एमएसए) भारतीय कंपनी (जिससे माल शुरू में आयात किया गया था) के साथ भारत में मरम्मत करने के लिए शर्तों को परिभाषित करते हुए ईएमएस समझौता/मास्टर सेवा समझौता/अनुबंध किए गए हो।

3. भारतीय निर्यातक द्वारा वचन—पत्र

आवेदक निर्यातक से एक वचन—पत्र (फर्म के शीर्ष—पत्र पर विधिवत हस्ताक्षरित और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगा) जिसमें यह विवरण हो कि:

- क. मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली आयातित मदों का विवरण, उनके स्कोमेट श्रेणी/उप—श्रेणी संख्या (संख्याओं), मात्रा, मद विवरण और विदेश के ईसीसीएन (यदि उपलब्ध हो) के साथ;
- ख. वह मद (मदों) विदेशों में (भारतीय कम्पनी के साथ अनुबंध करने वाली भारतीय कम्पनी की प्रत्यक्ष सहायक/मूल कम्पनी या भारतीय कम्पनी की विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी/विक्रेता/मूल उपकरण विनिर्माता) केवल संबंधित इकाईयों^० और मरम्मत आपूर्ति श्रृंखला^१ को निर्यात की जा रही हैं, जहां से इसे मूल रूप से मरम्मत और वापसी के उद्देश्य से आयात किया गया था।
- ग. आयात के बाद मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मरम्मत कार्य के दौरान कोई मूल्यवर्धन नहीं किया गया है;
- घ. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत की अनुमति भारतीय निर्यातकों और इकाईयों के बीच आयात या संविदात्मक समझौते की शर्तों के तहत दी गई है, जहां से माल आयात किया गया था;
- ड. शिपिंग बिल और आगामी पुनः निर्यात के गंतव्य देश में प्रविष्टि बिल और डीजीएफटी द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी तिमाही आधार पर डीजीएफटी को प्रस्तुत की जाएगी;
- च. उन मदों का उपयोग सैन्य अनुप्रयोगों के लिए या विक्रियता करने, अधिग्रहण करने, निर्माण करने, रखने, परिवहन, हस्तांतरण या उपयोग, रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों या ऐसे हथियारों की डिलीवरी करने में सक्षम मिसाइल के लिए नहीं किया जाएगा;

4. प्रमाणित/अनुमोदित आंतरिक अनुपालन कार्यक्रम या विदेशी कम्पनी के आईसीपी के अनुपालन का प्रदर्शन या उस कम्पनी के अनुपालन प्रबंधक द्वारा प्रमाणित आईसीपी [केवल अंतरा-कम्पनी हस्तांतरण के लिए]।
5. आईसीपी अनुपालन के साथ अधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) प्रमाणन [विक्रेताओं/ओईएम को पुनः निर्यात के लिए]

ग. जीएईआर के तहत मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के पुनः निर्यात के लिए पृच्छ रिपोर्टिंग

- i. भारतीय निर्यातक को जीएईआर के तहत स्कोमेट मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के निर्यात के प्रत्येक अंतरण/खेप का विवरण पिछली तिमाही में किए गए निर्यात के संबंध में प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के महीने के अंत तक बैमासिक आधार (मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर) पर ई-मेल (scomet-dgft-pr@nic.in) अथवा डीजीएफटी द्वारा यथा निर्धारित एक प्रक्रिया द्वारा स्कोमेट प्रभाग, डीजीएफटी (मुख्यालय) नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा।
- ii. पश्च शिपमेंट के विवरण में ऊपर उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रविष्टि बिल (जहां भी उपलब्ध हो), शिपिंग बिल विवरण, वैध निर्यात लाइसेंस प्रति को प्रस्तुत करना शामिल होगा;
- iii. ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/या जीएईआर का निलंबन/निरसन और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

घ. निलंबन/निरसन

जारी किया गया जीएईआर प्रसार संबंधी सरोकार पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर या निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत न करने या इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों का अनुपालन न करने पर डीजीएफटी द्वारा निलंबित/निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

ड. सामान्य भार्ते

- i. रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों अथवा जनविनाशकारी अस्त्रों को पहुंचाने वाली मिसाइलों और उनकी डिलीवरी प्रणाली के निर्माण, विकास, प्राप्ति, विनिर्माण, अधिग्रहण, परिवहन, अंतरण और/या प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के मामले में जीएईआर जारी नहीं किया जाएगा;
- ii. यूएनएससी व्यापार प्रतिषेध या प्रतिबंधित सूची के तहत शामिल देशों अथवा इकाइयों या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के विचार के आधार पर प्रसार संबंधी सरोकार के जोखिम के लिए मूल्यांकन किए गए देशों या इकाईयों हेतु जीएईआर जारी नहीं किया जाएगा।
- iii. डीजीएफटी जीएईआर जारी करने से इनकार करने या जीएईआर को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

च. पहले निर्यात/शिपमेंट के बाद आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना, आयात किए गए सामानों से उसी इकाई को निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्रों को प्रदान करने के लिए आवेदनों को आईएमडब्ल्यूजी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। असाधारण मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो जीएईआर जारी करने से पहले आईएमडब्ल्यूजी के साथ परामर्श किया जा सकता ह।

छ. ऐसे सभी प्राधिकार-पत्रों को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि के लिए आईएमडब्ल्यूजी की बाद की बैठक में उसके समक्ष लाया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीएईआर) की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैराग्राफ 10.12(घ) में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों से भारत में मरम्मत के बाद संबंधित इकाइयों और अधिकृत विक्रेताओं/ओईएम को स्कोमेट वस्तुओं के कई बार पुनः निर्यात की प्रक्रिया सरल हो गई है, जिसके लिए प्रत्येक पोतलदान के लिए नए अनुमोदन की आवश्यकता के बजाय तिमाही पोश्च-रिपोर्टिंग के साथ एक बार का प्राधिकार-पत्र दिया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th March, 2025

No. 50/2024-25

Subject:- Amendment to Para 10.12(D) of the Handbook of Procedures 2023 – Revised Procedure for General Authorization for Export after Repair (GAER)

F. No. 01/91/180/18/AM-17/EC(S).—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby inserts a new entry at Paragraph 10.12(D) under the Handbook of Procedures(HBP) 2023 with immediate effect.

2. Para 10.12(D) of the HBP 2023 is amended as under:

D. Authorization for export of same imported SCOMET items to Related entities⁰ and Repair supply chain¹ in the foreign country under General Authorization for Export after Repair(GAER)

⁰Related entities mean Direct subsidiary / Foreign Parent of the Indian Company or another Subsidiary of the foreign parent of the Indian Company.

¹Repair supply chain means (i) Authorized Vendor (ii) Original Equipment Manufacturer(OEM) with whom Indian company has a Master Service Agreement/Electronic Manufacturer Service agreement/Contract Agreement defining conditions of undertaking repair in India.

A. Export of imported SCOMET items **to the related entities⁰ and repair supply chain¹ in the foreign country** after repair in India will be allowed on the basis of a one-time General authorization for Export after Repair in India (GAER) subject to post reporting on quarterly basis issued by DGFT, subject to the following conditions:

- a. The SCOMET items were imported to a designated/authorized repair facility in India for the purpose of repair under a contract agreement/Master Service agreement (MSA)/Electronic Manufacturer Agreement (EMS); *or* Imported under a contract agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and entity abroad defining ‘Statement of Work (SOW)’/ ‘Scope of Work’ including conditions for undertaking repair in India;
- b. The items are to be re-exported to **only related entities⁰ and repair supply chain¹ in the foreign country**.
- c. The exporter is required to register and obtain General authorization for export after repair only once during the validity period. Subsequent export/re-export is subject to post reporting;
- d. The exporter is required to provide Bill of Entry for the imported item while applying for GAER for the first shipment.
- e. General authorization for export after repair shall be valid for a period of one year from the date of issue of General authorization subject to subsequent post reporting(s) within 30 days from the date of such export;
- f. Subsequent export would be allowed to the same entity and location to which the license has originally been issued. Note: Same entity would imply that (a) foreign buyer (b) consignee or intermediaries, if any (c) the end user are exactly the same for which authorisation has been issued to the applicant exporter.
- g. There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s) after repair and no value addition has been done during the repair work;
- h. No Export Authorisation would be granted when the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by country of import;
- i. No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- j. No details of ‘End Use’ and ‘End Use Certificate’ would be required;
- k. GAER issued for specific item and specific entity (buyer/end user) shall not be applicable in case the re-export is of a different imported item or to a different entity or Authorised OEM. In such cases, either a new GAER authorization may be applied or application may be filed under Para 10.12(D) of HBP.
- l. **Certified / approved Internal Compliance Programme or demonstrating compliance to the ICP of the foreign company or ICP certified by the compliance manager of that company shall be mandatory. [only for intra-company transfers].**
- m. **Authorized Economic Operator (AEO) Certification along with ICP compliance shall be mandatory. [for re-export to vendors/OEMs].**

B. Documents Required for GAER

1. Proof of import of the item(s):

- a. Export Authorisation (if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;
- b. Documentary proof and/or self-declaration that the item exempted from license requirement or place under no license requirement for India.
- c. Bill of Entry (first time)

2. Proof of obligation for repair of defective/damaged items:

Contract agreement and/or ‘Statement of Work (SOW)’/ Master Service agreement (MSA) between Indian exporter and with the entity abroad/**Direct subsidiary/Parent of the Indian Company or another subsidiary of the foreign parent of the Indian Company/Authorised Vendor/Original Equipment manufacturer having EMS agreement/Master service agreement/ contract with Indian Company** from (which the goods were imported initially) defining conditions for undertaking repair in India

3. An Undertaking from the Indian exporter:

An Undertaking from the applicant exporter (on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory) stating:

- a. Details of imported items to be exported after repair along with their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity, item description and ECCN of foreign country (if available) ;
- b. That item(s) are being exported to only **related entities⁰ and repair supply chain¹ in the foreign country (Direct subsidiary/Parent of the Indian Company or another Subsidiary of the foreign parent of the Indian Company/Vendor/Original Equipment manufacturer having contract with Indian Company)** from which it was originally imported for repair and return purpose.
- c. That there has been no change to the original characteristics/specifications of the item(s) after import and no value addition has been done during the repair work;
- d. That the repair of defective/damaged items is allowed under the conditions of import or contractual agreement between Indian exporters and entities from which goods were imported.
- e. That Shipping Bills and Bill of Entry into destination country of subsequent re-exports and any other information as sought by DGFT shall be submitted to DGFT on quarterly basis.
- f. That items would not use for military applications or to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use, chemical, biological, nuclear weapons or for missile capable of delivering such weapons.

4. Certified/approved Internal Compliance Programme or demonstrating compliance to the ICP of the foreign company or ICP certified by the compliance manager of that company. [only for intra-company transfers]

5. Authorized Economic Operator (AEO) Certification along with ICP compliance. [for re-export to vendors/OEMs]

C. Post reporting for re-export of items/software/technology under GAER

- i. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each transfer/consignment of exports of SCOMET items/software/technology under GAER to the SCOMET Division of DGFT (HQ), New Delhi, via e-mail (scomet-dgft@nic.in) or a procedure as prescribed by DGFT, on quarterly basis (March/June/September/December), by the end of subsequent month of each quarter, in respect of the exports made in the previous quarter.
- ii. The post-shipment details shall include submission of Bill of Entry (wherever available), shipping bill details, valid export license copy within the timelines mentioned above.
- iii. Failure to do so may entail imposition of penalty and/or suspension/revocation of GAER and action as per FT(D&R) Act.

D. Suspension / Revocation

GAER issued shall be liable to be suspended / revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory reports /documents within the prescribed timelines, or for non-compliance with the conditions of this Public Notice.

E. General conditions

- i. GAER would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and/or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
 - ii. GAER would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo/sanctions or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.;
 - iii. DGFT shall reserve the right to deny issuance of GAER or recall GAER.
- F. Applications for grant of General authorizations for export to the same entity from goods were imported shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members after the first export/shipment. In exceptional cases, consultation with IMWG may be done prior to issuance of GAER, in case required.
- G. All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

Effect of this Public Notice: Paragraph 10.12(D) of HBP 2023 has been amended to allow General Authorization for Export after Repair (GAER). The revised provisions streamline the procedures for multiple re-exports SCOMET items to related entities and authorized vendors/OEMs after repair in India under a one-time authorization with quarterly post-reporting instead of requiring fresh approvals for each shipment.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.